भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ को देश के हर क्षेत्र में बढ़ते फासीवादी आक्रमण तथा जनता पर जारी बर्बर सैनिक अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-2017' को पूरी तरह से विफल कर देने के संकल्प के साथ 21 सितम्बर से 27 सितम्बर यानी एक सप्ताह भर मनाएं!

90 प्रतिशत जनता की नई जनवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से नयी-नयी सफलताएं हासिल करने के मार्ग पर दृढ़ कदम से आगे बढ़ें!

पूर्वी रीजनल ब्यूरो

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ को देश के हर क्षेत्र में बढ़ते फासीवादी आक्रमण तथा जनता पर जारी बर्बर सैनिक अभियान 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-2017' को पूरी तरह से विफल कर देने के संकल्प के साथ 21 सितम्बर से 27 सितम्बर यानी एक सप्ताह भर मनाएं!

90 प्रतिशत जनता की नई जनवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से नयी-नयी सफलताएं हासिल करने के मार्ग पर दृढ़ कदम से आगे बढ़ें!

प्यारे जनता और प्यारे कामरेडो,

हम सबों की पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ को, 21 सितम्बर से 27 सितम्बर तक मनाए जाने का समय आ गया है। पिछले 13 वर्षों के दौरान हजारों-हजार शहीदों के शहादत व कुर्बानी के रक्त-रंजित पथ को पार कर पार्टी व जारी जनयुद्ध को मौजूदा मुकाम पर पहुंचा देने का इतिहास यही साबित करता है कि भारत के मजदूर-किसान सहित 90 प्रतिशत जनता के हित में काम करनेवाली पार्टी- एकमात्र भाकपा (माओवादी) ही है।

हमें भली-भांति मालूम है कि जिनके दिखाए हुए मार्ग और सूत्रबद्ध की गयी लाइन व नीति पर आगे बढ़ते हुए आज वर्ग-युद्ध के इस मुकाम पर हम पहुंचे हुए हैं, वे हमारे पार्टी के संस्थापक व मार्गदर्शक नेता और भारतीय क्रांति के अमर शहीद कामरेड चारू मजुमदार व कामरेड कन्हाई चटर्जी की देन है, इसलिए हमारे संस्थापक, शिक्षक व नेता कामरेड सीएम व कामरेड केसी को

इआरबी सहित हम सभी कामरेड शत्-शत् लाल सलाम पेश करते हैं। साथ-ही ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह के समय से लेकर आज तक यानी पिछले पांच दशकों के दौरान अपने प्राणों को न्योछावर किए 15 हजार से भी अधिक शहीदों को भी लाले लाल, लाल सलाम पेश करते हैं। साथ ही उत्पीड़ित राष्ट्रीयता की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार हासिल करने के आंदोलन के दौरान शहादत दिए तमाम शहीदों को भी शत्-शत् लाल सलाम पेश करते हैं।

पार्टी की 13वीं वर्षगांठ के अवसर पर इआरबी, इसके अधीन तमाम स्तरों की पार्टी कमेटी, पीएलजीए, आर.पी.सी.-के.के.सी. सहित जन-संगठनों के सदस्यों को, जो लोग मौजूदा चुनौती भरी परिस्थिति, चरम फासीवादी आक्रमण व घृणित आत्मसमर्पण-नीति और अन्यायपूर्ण युद्ध का साहस के साथ दृढ़ मुकाबला कर जारी न्यायपूर्ण युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी को हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन व गरमजोशी भरा लाल सलाम और शाबशी पेश करती है।

13वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न जेलों में दीर्घ दिन से बिना विचार की हालत में बंदी जीवन बिता रहे और विचार-व्यवस्था के वर्गीय आचरण के कारण फांसी की सजा व आजीवन कारावास से लेकर विभिन्न समयावधि की सजा भुगत रहे तमाम पार्टी सदस्य, समर्थक जनता व आम जनता को इआरबी हार्दिक क्रांतिकारी अभिवादन व तहे दिल से लाल सलाम पेश करती है। साथ ही साथ हमारे समग्र क्रांतिकारी आंदोलन के अभिन्न अंश के बतौर जेल आंदोलन को मानते हुए उसके प्रति पूरा समर्थन व एकजुटता प्रदर्शित करती है तथा 'तमाम राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त अविलम्ब रिहा करें' के नारा को जोरदार ढंग से बुलंद करती है।

कामरेडो और दोस्तो,

आपलोगों को भलीभांति मालूम है कि चूंकि हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) जन-मुक्ति का एकमात्र सही मार्ग यानी 'नक्सलबाड़ी एक-ही रास्ता' जो दरअसल सशस्त्र कृषि क्रांति तथा दीर्घकालीन जनयुद्ध का मार्ग होता है, उस पर, अग्रसर होने के लिए जनता की रहनुमाई की भूमिका निभा रही है; इसलिए

एकदम शुरूआत से ही क्रांतिकारी आंदोलन को शक्तिशाली दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा बर्बर पुलिसिया 'घेरा डालो व विनाश करो' अभियान को झेलना पड़ रहा है, भारी से भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। फिर भी, विपरीत में, क्रांतिकारी जनता भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई नहीं है। कम आत्मगत शक्ति होने के बावजूद वे लड़ रही हैं। 'खुद की समस्या खुद हल करो' के विचार से लैस होकर प्रतिवाद आंदोलन से शुरू कर विभिन्न प्रकार के जुझारू प्रतिरोध और सशस्त्र प्रतिरोध संघर्ष का संचालन कर रही हैं। चूंकि भारत की जनता क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रही हैं और भाकपा (माओवादी) नेतृत्व दे रही है; इसलिए पार्टी को पूरी तरह से नाश करने के बुरे इरादों से दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा है 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से एक बर्बर सामरिक अभियान तथा चौतरफा हमले का एक क्रूर युद्ध-अभियान।

जाहिर है कि ब्राह्मणीय हिन्दुत्ववादी मनुवादी दर्शन व विचारों से लैस बीजेपी की मोदी सरकार गद्दी पर बैठने के साथ-साथ उक्त 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' का तीसरा चरण जिसका अभी का स्वरूप मिशन-2017 को शुरू किया। मिशन-2017 में मुख्य केन्द्रीकरण केन्द्रीय कमेटी और विभिन्न स्पेशल एरिया कमेटी, राज्य कमेटियों के सदस्यों की हत्या के लिए और साथ-साथ डीके-बीजे-पूबि-पूझा-ओड़िशा-बीजेओ पर केन्द्रीकृत कर हमले होंगे। मतलब 2017 के अंदर पूरी पार्टी व जारी जन-क्रांति को ध्वस्त कर देने का विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद का निर्देशन पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने जो प्रतिक्रांतिकारी योजना बनाई है, उसी को कार्यान्वित करने के मकसद से चरम फासीवादी व बर्बर तरीके अपना कर ही अभियान को चलाया जाना है।

ऐसी स्थिति पूरे भारत के पैमाने पर कठिन दौर और कुछ जगहों में पीछे धक्का खाने वाली हमारी पार्टी व आंदोलन को उक्त मिशन को विफल कर देने के लिए उचित कार्यनीति अपनाने की जरूरत को दर्शाती है। ऐसी कार्यनीति का सफल कार्यान्वयन की ताजा मिसाल है दण्डकारण्य के वीर कामरेडगण व वीर जनता द्वारा चलाया गया फिलहाल की कुछ शानदार जवाबी कार्रवाइयां और बीजे-पूबी-पूझा-ओड़िशा-बीजेओ इत्यादि क्षेत्र में जारी प्रतिरोध कार्रवाइयां, जो दुश्मन को भारी चिंतित कर डाली। बाद में, केन्द्रीय गृहमंत्री की उपस्थिति में

देश के सुरक्षा सलाहकार, पुलिस, अर्द्ध-सैनिक बल व मिलिटरी, तमाम प्रकार के खुफिया विभाग इत्यादि तमाम विभागों के सबसे उच्च ओहदे के अफसरों को लेकर आयोजित एक बैठक के जरिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव लाकर उसके अधीन कुछ नयी कार्यनीतियां ग्रहण कर उसे और आक्रामक स्वरूप दिए जाने का प्रयास किया गया। जैसे:-

1. क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में तथा सीमा से सटे हुए राज्यों के सीमाक्षेत्र में संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर कॉरपेट सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
2. विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी शक्तियों का सफाया करना।
3. खुफिया नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए एस.पी.ओ., कोवर्टों, और पहचान करने वालों को और अधिक संख्या में तैयार करना और साथ ही साथ टीपीसी, जेजेएमपी, पीएलएफआई, जेपीसी, शांति सभा, ग्राम रक्षा दल, नागरिक सुरक्षा समिति इत्यादि प्रतिक्रांतिकारी गिरोहों का निर्माण व संचालन करना।
4. एक के बाद एक लगातार 'घेरा डालो- विनाश करो' के बर्बर सैनिक अभियान को ड्रोन व हेलिकॉप्टर सहित वायुसेना की निगरानी व्यवस्था की मदद लेकर उसे और तेज करना।
5. सड़क, रेल मार्ग, सूचना-तंत्र-इत्यादि का विकास करना।
6. बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक युद्ध और आत्मसमर्पण के कार्यक्रमों को अंजाम देना तथा विभिन्न स्तरों के नेतृत्वकारी कामरेडों को गिरफ्तार करवा देने पर लाखों-करोड़ों इनाम की राशि की खुली घोषणा करना।
7. कुर्की-जब्ती के नाम पर घर के तमाम कुछ को लूट लेना और खिड़की, दरवाजा, छत आदि को पूरी तरह तोड़-फोड़ देना और ऐसा कि घर सहित तमाम सामानों को आग के हवाले कर देना- इत्यादि, इत्यादि।

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि दुश्मन का मौजूदा ताकतवर पक्ष क्या एकमात्र, परम और अपरिवर्तनीय है? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ने हमें सिखाया है कि हर वस्तु या घटना के अंदर 'दो विपरीत चीजों की एकता' का नियम ही बरकरार रहता है। इसीलिए हर वस्तु या घटना को 'एक को दो में विभाजन' करके ही उसके बारे में सही विश्लेषण के जरिए उसमें निहित दोनों पक्षों का ठोस मूल्यांकन किया जा सकता है। इस नियम का इस्तेमाल करके ही दुश्मन की ताकतों को ठोस रूप से आंका जा सकता है और अभी-अभी के समय में कौन-सा पहलू प्रधान है व कौन-सा पहलू गौण है, उसे भी सही तौर पर तय किया जा सकता है।

परंतु ऐसा कर पाने में अक्सर हम कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं और एकांगीपन का शिकार हो जाते हैं। तब, कभी दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने और कभी कम करके आंकने- यह दो प्रकार की गलती हो जाती है। साथ ही साथ सब कुछ को सापेक्ष या तुलनात्मक रूप से न देखने व विचार न कर पाने की गलती भी हो जाती है। तब हमारे अंदर दो प्रकार के गलत चिंतन पैदा होते हैं। पहला, दुश्मन की ताकत को ज्यादा करके आंकने, जो हमारे अंदर शिथिल, निष्क्रिय व निराशा की मानसिकता पैदा करती है और कम शक्ति लेकर शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते हैं, जैसा चिंतन का पैदा करता है। दूसरा, दुश्मन की ताकत को छोटा करके आंकने की कमी, जो हमारे अंदर कुछ हठधर्मी या अराजक चिंतन जैसा वाम भटकाववादी चिंतन को पैदा करता है। पहला वाला दक्षिण भटकाव और दूसरा वाला 'वाम' भटकाव की ओर हमें ले जाता है। तब कभी हम केवल प्रतिकूल पहलू तो कभी केवल अनुकूल पहलू को ही एकमात्र जैसी सोच लेते हैं और उचित व सही कार्यनीति का निर्धारण करने में अक्षम साबित होते हैं।

उपरोक्त 'दो विपरीत चीज की एकता' और 'एक को दो में विभाजन' के नियमों को व्यवहार में लागू करके ही हम मौजूदा प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर विपरीत रूप से निहित अनुकूल पहलू को ढूंढ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ और एक बात हमें समझना है कि दुश्मन द्वारा हम पर तीव्र हमले व चरम

फासीवादी आक्रमण चलाने की कार्रवाई कतई उसके ताकतवर पहलू को नहीं दर्शाता है, बल्कि हकीकत में यह उसके भीतर से कमजोर होते रहने के पहलू को ही उजागर करता है।

उल्लिखित बातों के बारे में गहरी समझदारी हासिल कर पाने से ही हम मिशन-2017 हो या जारी अभूतपूर्व आक्रामक कार्यवाही हो, उसे मुकाबला करने के लिए हमारी कार्यनीतियां व योजना क्या होगी- इसके लिए हमें अवश्य ही मौजूदा देश-दुनिया तथा अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर हमारे लिए अनुकूल पहलुओं को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतीत की गलतियों से सबक लेकर तथा अभी भी हमारे अंदर जो सारी कमजोरियां काम कर रही है, उसे दूर हटाकर और पार्टी को बोल्शेविकरण के जरिए और मजबूत बनाना भी बहुत जरूरी है।

जिन सभी बिन्दुओं पर हमारी कार्यनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी है, वे हैं:-

1. इआरबी अंतर्गत सभी राज्यों में पार्टी को लगातार बोल्शेवीकरण की प्रक्रिया के जरिए और मजबूत बना कर ही जारी सेट-बैक की स्थिति से पूरी तरह उबर आने का जोरदार प्रयास चलाना होगा,
2. दुश्मन के चौतरफा हमले के विरूद्ध चौतरफा मुंहतोड़ जवाबी हमले की योजना अपनानी होगी,
3. सैद्धांतिक व राजनीतिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति तथा सैनिक और सांगठनिक कार्यभार संबंधी कार्यनीति- इत्यादि मुख्य-मुख्य कार्यनीति की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यनीतियों को सही समय पर तय नहीं कर पाने से अनुकूल परिस्थिति का फायदा हम उठा नहीं पाएंगे। हमें याद रखना होगा कि अगर क्रांतिकारी परिस्थिति का फायदा क्रांतिकारी नहीं उठाते हैं, तो प्रतिक्रांतिकारी लोग उसका फायदा अपने वर्ग-हित में पूरी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और क्रांति के बदले प्रतिक्रांति की लहर फैल जाती है।

वस्तुतः जवाबी कार्यनीतियों का निर्धारण करते समय हमें इस बात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि भाकपा (माओवादी) के गठन की शुरूआत से ही हमें एक के बाद एक 'घेरा डालो व विनाश करो' तथा 2009 से जारी 'ऑपरोशन ग्रीन हंट' जैसा बर्बर सैनिक हमले का लगातार सामना करना पड़ा व प्रतिरोध संघर्ष का भी संचालन करना पड़ा। इस दौरान हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। फिर भी हम टिके हुए हैं और आगे भी बढ़े हैं तथा बढ़ रहे हैं। हमारे अनुभव के भंडार में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के अनुभव मौजूद हैं। समय-समय पर हम हमारी पार्टी व आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए सकारात्मक व नकारात्मक पहलू का सटीक विश्लेषण कर पार्टी के अंदर निहित कमजोरी व गैर-सर्वहारा रूझानों के खिलाफ दोष निवारण आंदोलन चलाकर पार्टी को अधिक बोल्शेवीकरण करने की प्रक्रिया भी अपनाये हैं। एक ओर पार्टी को क्रमशः दोषमुक्त कर मजबूत करने और दूसरी ओर ग्रीन हंट के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक मुकाबला का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट के तीसरा चरण के तहत मिशन-2016 के भीषण सैनिक हमले के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध चलाते हुए जरूरत के तौर पर नये कार्यनीतियों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांगठनिक और प्रचार क्षेत्रों में शोषक-शासकों के काले कारनामों का उचित जवाब देते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बरकरार रख पा रहे हैं। ऐसा करके ही दण्डकारण्य, झारखण्ड, बिहार, प.बंगाल-ओड़िशा-झारखण्ड सीमा क्षेत्र, आंध्र-ओड़िशा सीमा क्षेत्र, ओड़िशा, महाराष्ट्र-गढ़चिरोली, पश्चिम घाटी आदि क्रांतिकारी आंदोलनों पर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए शासक वर्ग द्वारा लागू मिशन-2016 को हमने विफल किया है। अभी फिर से देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लक्ष्य से ही जारी मिशन-2017 के लिए अपनायी गयी प्रतिक्रांतिकारी योजनाओं का मुकाबला करने में प्रयासरत हैं।

वस्तुतः, हम मिशन-2017 को भी विफल कर सकते है। वशर्ते कि हम अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर निहित अनुकूल पहलू का फायदा उठाने में सक्षम हो सकें। इस विषय के मद्देनजर बहुत-ही संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू

परिस्थिति और उसमें निहित अनुकूल पहलुओं पर एक सरसरी नजर डालनी चाहिए। वे हैं:

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के कई पहलुवें:- जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज एक उथल-पुथल की स्थिति के अंदर से गुजर रही है। 2008 से खुद अमेरिका में शुरू हुआ वित्तीय संकट तुरंत ही तमाम साम्राज्यवादी देशों में फैल गया, जो आज भी एक गंभीर आर्थिक-राजनीतिक संकट के रूप में बरकरार है। फिलहाल, दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में विद्यमान चीन का एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी देश के बतौर आगमन होने के कारण साम्राज्यवादियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और तीखी हो गयी है और अनिवार्यत: साम्राज्यवादी देशों द्वारा एशिया-अफ्रीका-लातिन अमेरिका के तमाम पिछड़े हुए देशों में उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीति को जबरन थोप कर लूट-खसोट की मात्रा बहुत हद तक बढ़ा दी गयी है। खासकर पूंजी निवेश, खनिज सम्पदा सहित तमाम प्राकृतिक सम्पदा की लूट, सस्ता श्रमशक्ति, मालों का बाजार के रूप में लूट की चरागाह बना दी गयी है। फिर, अपनी लूटपाट की जगहों की वृद्धि करना, प्रभावाधीन इलाके को बढ़ाना तथा विश्व-बाजार का दखल व पुनर्दखल करना इत्यादि को लेकर साम्राज्यवादियों के बीच तीखा छीना-झपटी व कुत्तों की लड़ाई जारी है। मौजूदा समय में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के कई जगहों में साम्राज्यवाद द्वारा प्राक्सि युद्ध या स्थानीय युद्धों का उकसावा देना और खासकर पश्चिम एशिया, अरब देश व अफ्रीका के कई देशों में अपनी-अपनी सशस्त्र सेना का गठन कर पूरे देश को मार-दंगा-हत्या-पल्टा हत्या के स्थान में बदल दिया गया। जिसके कारण हजारों-लाखों की संख्या में हत्याकाण्ड और व्यापक संख्या में महिलाओं की इज्जत लूटे जाने की घटनाएं बेरोकटोक जारी है। सीरिया, लीबिया, यमन आदि देश इसकी ताजा मिसाल है और अफगनिस्तान व इराक तो अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा हजारों-लाखों टन बम गिराए जाने के कारण खंडहर में बदल गया है और अभी अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पूरे ईरान व उत्तर कोरिया को भी खंडहर में बदल देने की धमकी दी जा रही है। फलस्वरूप, साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्रों और जनता के बीच अंतरविरोध और तीखा हुआ है तथा रोज दिन उसमें

और वृद्धि हो रही है।

फिर साम्राज्यवाद का गहराता हुआ वित्तीय संकट के कारण जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों के शासक वर्ग द्वारा इस संकट से निपटने के लिए लागू की गयी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक नीतियां विफल हो गयी है। इसके कारण इन सभी देशों में बेरोजगारी प्रबल हो गयी है, आर्थिक विकास में मंदी आयी है, मजदूर-कर्मचारियों के वेतन में और नौकरियों व जन-कल्याण योजनाओं में भारी कटौती की जा रही है। इसके साथ-साथ अन्यान्य अनेक आर्थिक व राजनीतिक कारणों से पूंजीवादी देशों में पूंजीपति व मजदूर या सर्वहारा वर्ग के बीच का अंतरविरोध क्रमशः और तीव्र होता जा रहा है।

अभी के समय में विश्व-पटल पर नजर दौड़ाने से जो विशिष्ट पहलुवें दिखाई पड़ती हैं, वे हैं:-

i. एकल महाशक्ति के बतौर अमरीकी साम्राज्यवाद खुद की भूमिका को बरकरार रखने में अक्षम साबित हो रहा है और नाटो गठजोड़ के देशों को शामिल किए बिना कोई भी आक्रामक कार्रवाई में नहीं उतर पा रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का आगमन होने से विरोधी देशों पर बम गिराने व युद्ध थोपने की लफ्फाजी चला रहा है। पर ये सब अभी तक फालतू बात ही साबित हुई है। फिलहाल, अमेरिका व पूरे यूरोप में 'नस्लवाद', 'उग्र राष्ट्रवाद' व 'फासीवाद' का पुनः तेजी से उभार हो रहा है।

ii. रूस और चीन-दोनों शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों को बतौर एक गंठजोड़ उभर आने और शंघाई को-ऑपरेशन व ब्रीक्स गठबंधन के नेतृत्वकारी ताकत होने के कारण अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ प्रतिस्पर्धा व अंतरविरोध क्रमशः तीव्रतर होते जा रहा है। खासकर रूस के साथ यूक्रेन व सीरिया और रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों को लेकर तथा चीन के साथ दक्षिण सागर पर आधिपत्य विस्तार व दक्षिण कोरिया में मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के निर्माण

को लेकर तीखा विरोध जारी है;

iii. पिछड़े देशों में पूंजी निवेश, संसाधनों व बाजारों को लूटने के लिए तथा दुनिया को पुनर्विभाजित करने के लिए तमाम साम्राज्यवादी देशों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि होना;

iv. पिछड़े हुए देशों में अपनी पिट्ठू दलाल सरकार की स्थापना प्रभावाधीन इलाके को न केवल बनाये रखने बल्कि और विस्तार करने के लिए एक देश के साथ दूसरे देश को लड़वा देना, एक-एक देश में अपना-अपने सशस्त्र गिरोहों का निर्माण करते हुए पूरे तौर पर मार-दंगा का भयंकर स्थिति पैदाकर लूट, बलात्कार, हत्या तथा नरसंहार कर लाशों के ढेर में बदल देना तथा कई स्थानों में स्थानीय युद्ध का संचालन करते हुए पूरे देश को खंडहर में बदल देना और अमरीकी साम्राज्यवाद का मददपुष्ट यहूदीवादी इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर लगातार हमलों का संचालन करते हुए उनके भूभाग पर कब्जा जमाने का लगातार प्रयास जारी है।

उपरोक्त तीन मुख्य-मुख्य अंतरविरोध और इसके अंदर साम्राज्यवाद के साथ उत्पीड़ित राष्ट्र व जनता का विरोध प्रधान व निर्णायक होने के कारण विभिन्न रूपों के प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध, विद्रोह, क्रांति, राष्ट्रीय व जनवादी क्रांति तथा राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध इत्यादि मौजूदा दुनिया में प्रधान रूझान के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, यही हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के अंदर अनुकूल पहलू होता है।

घरेलू परिस्थिति के कई पहलुवें:-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन सालों से लागू किये जाने वाली सभी मनुवादी ब्राह्मणीय हिन्दुत्ववादी फासीवादी नीतियों का उद्देश्य है साम्राज्यवादी और सामंती वर्गों के हितों को आक्रामक रूप से पूरा करना। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए अपनायी गयी नीतियों से देश के अंदर सभी तबकों पर अंतरराष्ट्रीय पूंजी के

हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लागू सभी फासीवादी नीतियां देश के मजदूर-किसान-मेहनतकश जनता सहित सभी उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रों, उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदायों के खिलाफ है। इसलिए देश में मजदूर, किसान, निम्नपूंजीपति वर्ग, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्रों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासी, महिलाएं - सभी लोगों के लिए ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ लड़ने की स्थिति पैदा हुई है। मनुवादी हिन्दुत्ववादी फासीवाद मजदूर-किसान मेहनतकश जनता सहित तमाम उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित राष्ट्रों और उत्पीड़ित सामाजिक जनसमुदायों के लिए देश के सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की स्थिति पैदा कर दी, जो देश के राजनीतिक घटनाक्रम में नया बदलाव है।

पिछले तीन सालों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी ताकतों का गौ-रक्षा के बहाने देश भर में दलितों और मुसलमानों पर किये जाने वाले हमलों में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर गुजरात के उना तक हुए इन हमलों की पृष्ठभूमि में धर्मोन्मादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए दलित और मुसलमानों के साथ आदिवासी और पिछड़ी जातियों की शक्तियां उना में गोलबंद होकर हिन्दू धर्मान्धता का मुकाबला करने की कार्य-योजना बनायी। आगामी दिनों में ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवाद के खिलाफ मजदूर-किसान तथा तमाम जनवादी व क्रांतिकारी शक्तियां, दलित, मुसलमान, आदिवासी और अन्य प्रगतिशील तबकों के लिए और संगठित होकर जुझारू संघर्षों के लिए तैयार होने की परिस्थितियां बढ़ रही है।

देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के हित में, देश में आदिवासी इलाकों से प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कोशिशों की वजह से आदिवासी जनसमूह विस्थापन की गंभीर समस्या का सामना कर रही है और ऐसा कि आदिवासी जनता को अपने अस्तित्व और अस्मिता को बचाये रख पाने के सामने भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

विस्थापन समस्या पर आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता जुझारू आंदोलनों

में उतर पड़े हैं। झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी कानून और संथाल परगना काश्तकारी कानूनों (सीएनटी व एसपीटी एक्ट) में सुधारों के खिलाफ आदिवासियों व मूलवासियों के जुझारू व सशक्त आंदोलन के कारण सरकार संशोधन वापस लेने को मजबूर हुए। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओड़िशा में पिछले साल कई जगहों पर आदिवासियों के विस्थापन विरोधी आंदोलन ने जुझारू रूप ले लिया। विस्थापन समस्या पर कई जगहों पर गैर-आदिवासी जनता भी जुझारू संघर्षों में आंदोलनरत है। इससे आगामी दिनों में आदिवासी और गैर-आदिवासी जनता के लिए विस्थापन विरोधी आंदोलनों में मजबूती से संगठित होकर जुझारू संघर्ष चलाने की दिशा में अग्रसर होने की संभावना है।

देश भर में सैकड़ों विश्वविद्यालयों और हजारों कॉलेजों में दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक छात्र सहित व्यापक छात्र समूह, शिक्षा के व्यवसायीकरण व भगवाकरण के खिलाफ संघर्षों में उतर पड़े हैं। साथ ही साथ व्यापक जनसमुदाय हिन्दुत्ववादी-फासीवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लागू साम्राज्यवाद और सामंतवाद परस्त नीतियों के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। आगामी दिनों में इसमें प्रगतिशील शक्तियों के शामिल होने के मौके बढ़ रहे हैं।

जब से केन्द्र में मोदी सत्ता पर काबिज है, तब से एक ओर देश को पूरी तरह साम्राज्यवादी निवेश के लिए हवाले करते हुए, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, देशभक्ति और देशद्रोह के अस्त्रों का प्रयोग कर लोगों के जनवादी अधिकारों पर हिन्दुत्ववादी गुण्डा गिरोहों द्वारा बेरोकटोक हमले होते जा रहे हैं। इसके विरोध में देश भर में जनवादियों और सच्चे देशभक्त ताकतों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में किसान विभिन्न रूपों में लड़ रहे हैं। साम्राज्यवाद के अनुकूल और किसान-विरोधी नीतियों की दुष्परिणामों की वजह से कृषि संकट गहराने के कारण जाट, पटेल, मराठा, कापु जैसे कृषि आधारित जातियों में भी लड़ने के लिए मजबूर होने की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं।

अमेरिकी साम्राज्यवादियों के आदेशों के सामने घुटने टेक कर पिछले साल केन्द्र सरकार द्वारा रक्षा, दवाई, सिंगल-ब्रांड खुदरा व्यापार, प्रसारण (रेडियो प्रसारण), नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रों में 100 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लगाने के लिए अनुमति दे दी गयी। इसके साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देशीय बड़े कार्पोरेट कंपनियों की हितों की रक्षा के लिए मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले श्रम कानूनों का केन्द्र सरकार ने मजदूरों के हित की रक्षा के नाम पर संसद से पारित करवा लिया। इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पिछले साल सितम्बर महीने में वामपंथी ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में देश भर में 15 करोड़ से ज्यादा मजूदरों ने आम हड़ताल की। इस साल 28 फरवरी व 22 अगस्त को देश भर में 10 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने श्रम कानूनों में सुधारों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग जैसे अन्य जनविरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ बंद का आयोजन किया। आगामी दिनों में मजदूर आंदोलन व मजदूरों के हड़तालों में अवश्य-ही बढ़ोत्तरी होगी। मोदी सरकार की नीतियां न केवल मजदूरों के खिलाफ है, बल्कि इससे छोटे व मध्यम किस्म के उद्योग भी दिवालिया का शिकार हो रहा है, इससे आगामी दिनों में छोटे व मध्यम पूंजीपति के लिए भी अलग-अलग रूपों में लड़ने की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।

फिलहाल, साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों के लिए पूरे देश को एक ही एकीकृत बाजार के रूप में ढालने के लिए परोक्ष कर नीति को सुधार कर वस्तु व सेवा कर (GST) को सामने लाया गया है। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का धोखेबाजी वाला प्रचार के साथ बड़े नोटों को रद्द कर लोगों के पास मौजूद पूरे पैसे को बैंकों में जमा करवाया गया। इससे मजदूरों, किसानों, आम जनता सहित छोटे व्यापारियों और छोटे पूंजीपतियों को झटका लगा। इससे कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को धक्का लगा। लोगों को अपने बचत पैसों को स्वतंत्र रूप से विनिमय करने का मौका न देकर उनके सभी पैसे बैंकों में जमा कराकर, इसके जरिए साम्राज्यवाद और दलाल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते हुए डिजिटलीकरण, नगदरहित अर्थ व्यवस्था स्थापित करने के लिए की जाने वाली कोशिशें आगामी दिनों में देश के मध्यम

वर्ग सहित सभी तबकों पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और दलाल नौकरशाही पूंजी के हमले और बढ़ने के आसार हैं।

मोदी सरकार द्वारा देश 'आर्थिक तौर पर विकसित हो रहा है' की लफ्फाजी किये जाने के बावजूद देश में औद्योगिक क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में मंदी की स्थिति पैदा हो गयी, इस कारण बेरोजगारी, महंगाई और कृषि संकट बढ़कर इस 'विकास' के खोखलापन का भण्डाफोड़ कर रहा है।

कश्मीर का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष पिछले साल से तेज होता जा रहा है। फिलहाल, इस संघर्ष में और एक बार उभार आया। इसमें जनता और एक बार ईट-पत्थर से लैस होकर व हथियारबंद होकर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ लड़ रही हैं। गौरतलब है कि इस संघर्ष में किशोर-युवा बड़े पैमाने पर शामिल हो रहे हैं। इस संघर्ष के लंबे दौर से गुजरने के आसार हैं। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सामने वहां लंबे समय तक फंस जाने की स्थिति पैदा हुई है। उत्तरपूर्व भारत में आत्मनिर्णय के अधिकारों के लिए संघर्षरत विभिन्न राष्ट्रीय मुक्ति संगठन फिर से संगठित और संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़ रहे हैं।

देश के अंदर दिन-ब-दिन तेज होने वाले तमाम मूल-मूल अंतरविरोधों के कारण उभरती सामाजिक लड़ाइयों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार कुछ और फासीवादी कानूनें सामने ला सकती है। इसी तरह विभिन्न नाम देकर हिन्दू फासीवादी गिरोहों को भी गठित करने और जनता पर गैरकानूनी एवं फासीवादी हमले तेज करने के आसार हैं।

कुल मिलाकर मौलिक अंतरविरोध तेज होते जाने के कारण आगामी दिनों में देशीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित राष्ट्र और उत्पीड़ित तबकों के लोग साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाही पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ व्यापक तौर पर आंदोलन में गोलबंद होंगे। इन संघर्षों से दुनिया भर में माओवादी पार्टियां/क्रांतिकारी पार्टियां गठित व संगठित होने के आसार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह स्थिति दुनिया भर के साम्राज्यवादियों सहित शोषक-शासक वर्गों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है।

घरेलू परिस्थिति के उपरोक्त पहलुओं के कारण यानी देश के अंदर मौजूद अभी-अभी के समय के सामंतवाद के साथ व्यापक जनता का, साम्राज्यवाद के साथ भारतीय जनता का, पूंजी के साथ श्रम का, शासक वर्गों के अपने बीच के, इन तमाम अंतरविरोधों का क्रमशः तीव्र व तीखा होने के कारण विभिन्न रूपों का प्रतिवाद, विक्षोभ, प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध व कृषि-क्रांतिकारी गुरिल्ला युद्ध तथा जनयुद्ध की प्रवृत्ति ही मुख्य रूझान के रूप में उभर रही है।

आह्वान

प्यारे कामरेडो और दोस्तो,

अंतरराष्ट्रीय व घरेलू परिस्थिति के अंदर जो अनुकूल पहलुवें दिखाई पड़ रही है, उसका सही-सही इस्तेमाल करके ही उसे क्रांति में बदल डालना संभव होगा। ऐसे कार्यभार को एक मजबूत व बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ही यानी मौजूदा समय में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ही सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती है। अगर ऐसा कर पाने में हम सक्षम होंगे, तब-ही भारतीय क्रांति के मौजूदा दौर को, तमाम विघ्न-बाधा यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट हो या उसके तहत मिशन-2017 हो, का उचित मुकाबला कर आगे की ओर, ऐसा कि अंतिम विजय की ओर बढ़ाकर ले जा सकते हैं।

अतः तमाम पार्टी सदस्य, आम कतार व क्रांतिकारी जनता के पास केन्द्रीय कमेटी के पूर्वी रीजनल ब्यूरो का आह्वान है कि क्रांतिकारी आंदोलनों का सफाया करने के बुरे इरादे से भारत के शासक वर्गों द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसा बर्बर सामरिक अभियान का खूंखार तीसरा चरण व उसके तहत मिशन-2017 को पूरी तरह विफल व परास्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक पार्टी नेतृत्व को बचाते हुए जारी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के फौरी कर्तव्यों का संचालन करें। साथ ही साथ जन-आधार को और विस्तार व मजबूत कर उस पर आधारित होते हुए जनयुद्ध-छापामार युद्ध का संचालन करें। दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाकर मौका मिलने के साथ-साथ पीएलजीए बलों को केन्द्रीकृत कर दुश्मन के एकल इकाइयों पर या उन्हें विभाजित कर हमला करते हुए उसे सफाया करने का प्रयास करें, हथियार जब्त करने का प्रयास करें।

इसके लिए छापामार युद्ध नियमों व उसूलों, गुप्तता, बिजली की रफ्तार व दृढ़संकल्प तथा स्थानांतरण के आत्मरक्षात्मक व आक्रामक कार्यनीतियों को पहलकदमी के साथ अमल करने का प्रयास करें। छापामार युद्ध को तेज व विस्तार करने का प्रयास करें। गांव-गांव व इलाके-इलाके में पार्टी, पीएलजीए, आरपीसी, केकेसी व विभिन्न जन संगठनों तथा संयुक्त मोर्चा को और मजबूत व विस्तार करने का प्रयास करें।

साथ ही साथ, पूरे देश-भर में जारी फासीवादी आक्रामक रवैया तथा फासीवादी आक्रमण के खिलाफ स्वतंत्र पहलकदमी व स्वतंत्र कार्यसूची के आधार पर कार्यक्रम के अलावा फासीवाद-विरोधी तमाम प्रकार की ताकतों के साथ-साथ तमाम प्रगतिशाील, जनवादी, आत्म-निर्णय के लिए संघर्षरत ताकतें तथा क्रांतिकारी ताकतों को लामबंद कर फासीवाद-विरोधी संयुक्त मोर्चा का, जितना जल्द संभव गठन करने के लिए अपनी पहलकदमी को तेज करें। बिहार-झारखंड के भूमिहीन गरीब किसानों को फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का निर्माण करें व तमाम राजनीतिक बंदियों की अविलंब बिना शर्त्त रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें।

इन सारे कुछ के अलावा, जल-जंगल-जमीन-इज्जत-तमाम अधिकार के लिए, भूमि अधिग्रहण व विस्थापन के खिलाफ, कृषि-समस्या व व्यापक किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या की समस्या के खिलाफ, व्यापक मजदूर-विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ, शिक्षा के व्यवसायीकरण व भगवाकरण के खिलाफ, इन सभी आंदोलनों को समर्थन व सहयोग देकर तथा उसमें शामिल होकर सारे आंदोलनों को एक महान सामाजिक क्रांति व बदलाव की धारा में ले जाने की भरपूर कोशिश करनी होगी।

रास्ता कठिन, जटिल, चुनौती भरा व टेढ़ा-मेढ़ा है। पर, मुक्ति के लिए, अधिकार व आजादी के लिए दूसरा कोई आसान रास्ता खुला हुआ नहीं है। अतः डर-भय त्याग कर प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार होना होगा। अगर हम सही लाइन, नीति, पद्धति व शैली पर अडिग रहेंगे, तो अंततः शोषक-शासकों की पराजय और शोषित-शासित व उत्पीड़ित जनता की जीत होकर ही रहेगी।

शोषक-शासक नहीं, बल्कि जनता केवल जनता ही इतिहास बनाने की मूल प्रेरक शक्ति है। नया इतिहास बन रहा है और बनता रहेगा। मौजूदा समाज जनता का जनवादी राज की स्थापना करते हुए समाजवाद व साम्यवाद स्थापित करने की ओर बढ़ेगा ही।

- ★ **मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिंदाबाद!**
- ★ **भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जिन्दाबाद!**
- ★ **हमारे पार्टी के संस्थापक, शिक्षक, पथ प्रदर्शक व महान शहीद कामरेड सीएम व केसी अमर रहें!**
- ★ **महान विश्व सर्वहारा क्रांति जिन्दाबाद!**
- ★ **मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद व सर्वहारा अंतरराष्ट्रवाद जिन्दाबाद!**
- ★ **भारत की नई जनवादी क्रांति जिन्दाबाद!**
- ★ **विश्व साम्राज्यवाद व संशोधनवाद मुर्दाबाद!**
- ★ **'ऑपरेशन ग्रीन हंट' व 'मिशन-2017' को पूरी तरह विफल करें!**
- ★ **आत्मसमर्पण नहीं, शहीदों के रक्तरंजित पथ पर आगे बढ़ें!**
- ★ **मनुवादी-हिन्दुत्ववादी फासीवाद के खिलाफ संभावित तमाम ताकतों को लेकर व्यापक संयुक्त मोर्चा का निर्माण करने के लिए सक्रिय प्रयास चलायें!**
- ★ **बिहार-झारखंड के भूमिहीन गरीब किसानों को फांसी की सजा दिये जाने के खिलाफ व्यापक जनांदोलन का निर्माण करें!**
- ★ **तमाम राजनीतिक बंदियों की अविलंब बिना शर्त्त रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें!**

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ

25 अगस्त, 2017

पूर्वी रीजनल ब्यूरो
भाकपा (माओवादी)